अफगान में शांति की संभावना

लेखक – गौतम मुखोपाध्याय (अफगानिस्तान में पूर्व राजदूत (2010-2013 तक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

14 सितम्बर, 2019

"अमेरिकी-तालिबान वार्ता के निलंबन ने शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए वैश्विक समुदाय और भारत के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है।"

9 सितंबर की सुबह (भारतीय मानक समय के अनुसार) एक विचित्र ट्वीट द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अफगानिस्तान में अमेरिकी विशेष दूत, जैल मे खालिल्जाद के नेतृत्व में तालिबान के साथ 'शांति' वार्ता को अचानक बंद कर दिया, जिसका कारण एक अमेरिकी सैनिक की हत्या बताया गया है और इसके लिए तालिबान को जिम्मेदार माना गया है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने गुप्त रूप से तालिबान और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को अलग से कैंप डेविड में सप्ताहांत में व्यक्तिगत रूप से एक सौदा करने के लिए आमंत्रित किया था। समझौता नौ दौर की वार्ता में हुआ था, मोटे तौर पर दोहा, कतर में। इस ट्वीट से पहले श्री खालिल्जाद ने श्री गनी और अफगानिस्तान की राष्ट्रीय एकता सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अब्दुल्ला को कई दौर की वार्ता के अंतरिम समझौते पर जानकारी दी। उन्हें इस अंतरिम समझौते को दिखाया जरूर गया लेकिन इसकी प्रति दी नहीं गई। समझौते का मुख्य विवरण दो सितंबर की शाम को एक निजी टेलीविजन चैनल पर सामने आया था, जिसमें 135 दिनों में पांच अफगानी ठिकानों से लगभग 14,000 अमेरिकी सैनिकों में से लगभग 5,400 की वापसी की बात कही गयी थी। 28 सितंबर को होने वाले अफगान राष्ट्रपति चुनावों से पहले अंतर-अफगान वार्ता को शुरू करने के लिए दो सप्ताह की कड़ी समयरेखा भी शामिल थी।

इस घोषणा के साथ ही हिंसा की लहर फैल गई, जिसके उत्तर में रणनीतिक प्रांतीय राजधानियों के खिलाफ अपराध और काबुल में आत्मघाती विस्फोट शामिल थे, और ये उस वक्त हुए थे जब श्री खालिल्जाद अपने टीवी साक्षात्कार को बीएस खत्म ही कर रहे थे। स्पष्ट रूप से ये हमले इसलिए हुए थे क्योंकि वे चुनाव होने नहीं देना चाहते थे।

बातचीत के रूप में सौदा एक तरफा, आंशिक और अत्यधिक त्रुटिपूर्ण था। यह श्री ट्रम्प के नवंबर 2020 तक सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लक्ष्य से संबंधित था, लेकिन यह यू.एस. के आतंकवाद के खिलाफ दी गयी गारंटी के मामले में कमजोर था और इसमें अफगानिस्तान की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सुरक्षा उपायों का अभाव था। श्री ट्रम्प के फैसले के कारणों में एक अवशिष्ट आतंकवाद-प्रतिरोधक (counter&terrorism) और खुफिया उपस्थिति शेष सैनिकों (8,600) की वापसी को लेकर अनसुलझे मतभेद और अमेरिका में महत्त्वपूर्ण स्तरों पर तालिबान में विश्वास की कमी शामिल थे।

व्यापक संघर्ष विराम को हिंसा में एक सीमित कमी के रूप में दिखाया गया। इसके अलावा, तालिबान दबाव में एक गैर-आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत को अफगान सरकार ने प्रभावी ढंग से कमजोर किया। अफगान सरकार जिसके साथ अमेरिकी द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और सुरक्षा समझौते थे, को दरकिनार और शक्तिहीन कर दिया गया था, जिसमें सार्वजनिक भावना यह थी कि अफगानिस्तान के भविष्य का निर्णय विदेशियों द्वारा लिए जा रहे हैं। इसके बाद सरकार को काफी प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा।

घोषणा का सबसे कपटपूर्ण पहलू इसका समय और चुनावों को कम आंकने और उन्हें निरर्थक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति चुनावों से कुछ दिन पहले ही इंट्रा-अफगान वार्ता शुरू करने का प्रयास था। यहाँ डर यह था कि सफल होने पर वे अंतरिम संक्रमणकालीन या शक्ति-साझाकरण की व्यवस्था को कमजोर करने की योजना बना सकते हैं, जो अमेरिकी सेनाओं को बाहर निकालने के लिए

शांति का भ्रम प्रदान करता। इससे भविष्य में सत्ता संभालने से पहले तालिबान के लिए एक प्रमुख पद का मार्ग प्रशस्त हो जाता और यह अफगानिस्तान को अस्थिरता की ओर धकेल देता, जो अप्रत्याशित परिणाम के साथ 1990 के शहर-मुजाहिदीन की लड़ाई से भी बदतर एक गृहयुद्ध बन जाता।

अधिक मौलिक रूप से, इस समझौते की अमेरिका के साथ-साथ अन्य जगहों पर भी व्यापक रूप से आलोचना की गई थी। इसे एक शांति समझौते के बजाय 'समझौतापूर्ण वापसी', ष्त्यागष और यहां तक कि एक 'आत्मसमर्पण' के रूप में देखा गया, जिसमें लोकतंत्र और महिलाओं की उन्नति सहित पिछले 18 वर्षों के राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक निवेशों और नागरिक लाभ का त्याग शामिल था, जो कि कट्टरपंथी चरमपंथ को बढ़ावा देने वाले गृहयुद्ध के लिए परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। अफगानिस्तान में, समझौते को व्यापक रूप से तालिबान और पाकिस्तान को अफगानिस्तान को बेचने और विश्वासघात के रूप में माना गया था। इसी चिंता को भारतीय भी गहराई से साझा करते हैं।

निर्णय के पीछे एक वृत्ति यह थी कि यह अमेरिका के लिए एक बुरा सौदा के रूप में था और तालिबान द्वारा बैठक से अधिकतम लाभ निकालने के प्रयासों के कारण उत्पन्न हुई झुंझलाहट भी थी।

हालांकि, अब अफगान और दुनिया राहत की सांस ले सकते हैं कि खलीलजाद सौदा अभी के लिए समाप्त कर दिया गया है, लेकिन यह अल्पकालिक भी हो सकता है। हालांकि, अभी भी आतंकवाद विरोधी रणनीति की जरूरत है जिसके लिए उसे विकल्प तलाशने होंगे। शांति प्रक्रिया की मांग भी रहेगी। कुछ महीनों में हालात फिर से बदल सकते हैं।

फिर भी, अमेरिकी-तालिबान वार्ता के निलंबन ने अफगान राष्ट्रपति चुनावों की पकड़ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत के लिए शांति और वापसी के लिए उनके दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने के लिए अवसर जरूर प्रदान किया है।

सबसे पहला, अफगान चुनाव अधिकारियों और सुरक्षा बलों को अफगान संप्रभुता के अभ्यास के रूप में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर तरह से समर्थन किया जाना चाहिए। सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की जानी चाहिए। तालिबान इसे बाधित करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन एक बहुत अच्छा मतदान भले ही सुरक्षित क्षेत्रों में ही हो, संवैधानिक व्यवस्था और इस्लामिक रिपब्लिक के लिए जीत सुनिश्चित करेगा।

दूसरा, इसका परिणाम तालिबान के साथ वार्ता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकता है जो अफगान के नेतृत्व वाले, अफगान-स्वामित्व वाले और अफगान-नियंत्रित होगा, न कि वाशिंगटन, इस्लामाबाद, दोहा या मास्को से। भारत को इस तरह की वार्ता का समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए।

तीसरा, चुनावों से मुक्त, अफगान सरकार को तालिबान के साथ बातचीत के पीछे एक राष्ट्रीय सहमति बनाने का बीड़ा उठाना चाहिए, जिसे अब तक यह करने में विफल रही है।

चौथा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस प्रक्रिया का समर्थन करना चाहिए और पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस से खुद को दूर करने, साथी अफगानों के खिलाफ हमलों को रोकने, युद्ध विराम के लिए सहमत होने और अफगान प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधे बातचीत करने के लिए तालिबान पर अपने प्रयासों का ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

पांचवां, तालिबान पर अमेरिकी सैन्य दबाव काफी नहीं है। दोहा वार्ता इस संदेह को दूर करती है कि अफगानिस्तान में शांति का मार्ग पाकिस्तान के माध्यम से है भले ही वह अमेरिकी था जो रियायतें दे रहा था। इसके लिए पाकिस्तान पर हर संभव साधनों का उपयोग कर दबाव डालना चाहिए। अफगानिस्तान के बेहतर भविष्य के लिए उसे आर्थिक रूप से अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है, जिसे कम बजट में सुरक्षा बलों के एक प्रगतिशील 'अफगानीकरण' के माध्यम से और राजस्व उत्पन्न करने के लिए अफगानिस्तान के खनिज क्षेत्र में निवेश के माध्यम से करना होगा और भारत इसमें मदद कर सकता है।

अंत में, भारत को अपनी नीतियों को प्रभावित करने और अफगानिस्तान में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक भूमिका निभाने के लिए श्री ट्रम्प और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तालमेल का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए।

GS World Committed to Excellence

अमेरिका-अफगानिस्तान युद्ध

चर्चा में क्यों?

- अफगानिस्तान में शांति को लेकर अमेरिका और तालिबान में हो रही बातचीत पर पूर्णविराम लगता दिख रहा है।
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस आतंकी संगठन के साथ लंबे समय से चल रही बातचीत बिना किसी नतीजे पर पहुंचे ही खत्म हो गई।
- इस बातचीत का अंत अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ होना था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'जहां तक मेरा सवाल है, वो (बातचीत) दफन हो चुकी है।'
- इस फैसले की वजह से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान द्वारा किए गए एक हमले को बताया गया है, जिसमें इस हमले में एक अमेरिकी सैनिक सहित 12 लोगों की मौत हो गई थी।
- अमेरिका की ओर से राजनयिक जैल मे खालिल्जाद अभी तक तालिबान के साथ नौ दौर की वार्ता कर चुके हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद साल भर से जारी इस वार्ता पर विराम लगता दिखाई दे रहा है।

पृष्ठभूमि

- तालिबान का उदय 90 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में तब हुआ जब अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सेना वापस जा रही थी। पश्तूनों के नेतृत्व में उभरा तालिबान, अफगानिस्तान के परिदृश्य पर 1994 में सामने आया।
- माना जाता है कि तालिबान सबसे पहले धार्मिक आयोजनों या मदरसों के जरिये उभरा जिसमें ज्यादातर पैसा सऊदी अरब से आता था।
- सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद वहाँ कई गुटों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था और मुजाहिद्दीनों से भी लोग परेशान थे।
- ऐसे हालात में जब तालिबान का उदय हुआ तो अफगान लोगों ने उसका स्वागत किया था।
- प्रारंभ में तालिबान को इसलिये लोकप्रियता मिली क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया, अव्यवस्था पर अंकुश लगाकर अपने नियंत्रण में आने वाले इलाकों को सुरक्षित बनाया ताकि लोग व्यवसाय कर सकें।
- दक्षिण-पश्चिम अफगानिस्तान में तालिबान ने जल्द ही अपना प्रभाव बढ़ाया। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान सीमा से लगे हेरात प्रांत पर कब्जा कर लिया।
- धीरे-धीरे तालिबान पर मानवाधिकार उल्लंघन और सांस्कृतिक दुर्व्यवहार के आरोप लगने लगे।
- 2001 में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद तालिबान ने विश्व प्रसिद्ध बामियान बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया।
- पाक-अफगान सीमा पर पश्तून इलाके के बारे में तालिबान का कहना था कि वह वहाँ शांति और सुरक्षा का माहौल बनाएगा और सत्ता में आने के बाद शरिया कानून लागू करेगा।
- पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों जगह तालिबान ने या तो इस्लामिक कानून के तहत सजा लागू कार्यवाही जैसे- हत्या के दोषियों को सार्वजनिक फाँसी, चोरी करने के दोषियों के हाथ-पैर काटना।
- दुनिया का ध्यान तालिबान की ओर तब गया जब न्यूयॉर्क में 2001 में हमले किये गए। अफगानिस्तान में तालिबान पर आरोप लगाया गया कि उसने ओसामा बिन लादेन और अल कायदा को पनाह दी है जिसे न्यूयॉर्क हमलों का दोषी बताया जा रहा था।

ट्रंप के फैसले पर संदेह क्यों?

- भले ही डोनाल्ड ट्रंप तालिबान के साथ चल रही वार्ता रोकने के पीछे की वजह काबुल में पिछले सप्ताह हुए हमले को बता रहे हों, लेकिन उनका यह तर्क अधिकांश लोगों के गले नहीं उतर रहा है।
- इसकी वजह यह है कि अमेरिका पिछले एक साल से तालिबान से बात कर रहा है और इस दौरान तालिबान के हमलों में कई अमेरिकी सैनिक और राजनयिक भी मारे गए।
- एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अब तक तालिबान के हमले में 16 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं।
- बीते महीने ही एक हमले में नाटो और अमेरिका के कई अधिकारियों की मौत हुई थी. जानकार सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जब साल भर से अमेरिकी सैनिक तालिबान के हमले में मारे जा रहे थे तब अमेरिका ने इस संगठन से बातचीत क्यों नहीं रोकी? ऐसे में अब अचानक एक हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता को रोकना समझ से परे है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **हाल ही में चर्चा में रहे अमेरिका-तालिबान वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

   1. यह तालिबान के साथ वार्ता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान कर सकती थी।
   2. इस शांति समझौते से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस हो जाती।
   3. अफगानिस्तान सरकार को शामिल किये बगैर कोई समझौता दीर्घावधि में विफलता का नतीजा साबित होगा।

   उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

   (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
   (c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **With reference to the recent US-Taliban talks, consider the following statements-**

   1. It could provide a strong basis for negotiations with the Taliban.
   2. With this peace deal, the US Army would have withdrawn.
   3. Any agreement without involving the Government of Afghanistan will prove to be the result of long term failure.

   Which of the above statements are correct?

   (a) 1 and 2 (b) 1 and 3
   (c) 2 and 3 (d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: अफगानिस्तान में स्थिरता हेतु अमेरिका-तालिबान शांति वार्ता की विफलता ने क्या भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय भूमिका निभाने का अवसर प्रस्तुत किया है? अपने मत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। (250 शब्द)

Q. Has the failure of the US-Taliban peace talks for stability in Afghanistan presented an opportunity for India to play an international role? Give an argument in favor of your opinion. (250 Words)

नोट : 13 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।